उग्रवादियों की गतिविधियों के संबंध में तमिलनाडु के मुख्य मंत्री को प्रधान मंत्री के साथ वार्ता

503. **श्री रजनी रंजन साहू** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने तमिलनाडु में उग्रवादियों की बढ़ती गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में अभी हाल में प्रधान मंत्री के साथ बातचीत की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री ने तमिलनाडु के मुख्य मंत्री से बातचीत की। विचार-विमर्श सामान्य प्रकार का था और तमिलनाडु में उग्रवादियों की गतिविधियों का मामला भी उठा

Safety and health considerations for construction workers

504. SHRI B. K. HARIPRASAD: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a lack of safety and health considerations in respect of construction workers in the country;

(b) what is the estimated number of construction workers males, females and children engaged in the country, State-wise; in Government and non-Government workers;

(c) the number of minor and major accidents/deaths occuring each year due to the lack of safety and health considerations; and

(d) whether Government would adopt the I.L.O. safety and health convention 1988 as a first step and also ensure medical insurance and safety of workers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI RAMJI LAL SUMAN): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) No such data is being collected by the Ministry.

(d) It may not be possible for the present to ratify the convention.

बोफोर्स तोप सौदे से संबंधित दस्तावेजों का भारत सरकार को सौंपा जाना

505. **श्री सुनील बसुराय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्विटजरलैंड सरकार ने बोफोर्स तोप सौदे से संबंधित दस्तावेज भारत सरकार को सौंप दिये हैं ; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री [illegible]) : (क) और (ख) स्विस जांच ब्यूरो के अनुसार "ज्यूरिच" बैंक में एक खाता (एकाउंट) संबंधी दस्तावेज स्विस अधिकारियों द्वारा सरकार को सौंप दिये गये हैं। मामला न्यायालय में निर्णयाधीन है इसलिये इस संबंध में ब्यौरे प्रकट नहीं किये जा सकते।

उल्फा के विरुद्ध कार्यवाही

506. **श्री शंकर दयाल सिंह :**
श्री जी०जी० स्वेल :
श्री गुरुदास दासगुप्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में विशेषकर राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के पश्चात उल्फा उग्रवादियों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई

में उग्रवादियों और सुरक्षा कर्मियों सहित कितने व्यक्ति मारे गये हैं और कितने घायल हुये हैं तथा अब तक कितनी गिरफ्तारियां की गई हैं और इन उग्रवादियों से कितने हथियार बरामद किये गये हैं ;

(ख) उग्रवादियों के ठिकानों से बरामद किये गये शवों की संख्या कितनी है और उनकी पहचान संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उल्फा उग्रवादियों की अनुमानित संख्या कितनी है ;

(घ) क्या इन उल्फा उग्रवादियों को विदेशों से सहायता मिल रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद मारे गये तथा घायल हुये, व्यक्तियों, बरामद किये गये शस्त्र तथा की गयी गिरफ्तारियों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

(1)	मारे गये सुरक्षा कर्मचारी	2
	घायल हुये सुरक्षा कर्मचादी	11
(2)	मारे गये उल्फा उग्रवादी	3
	घायल हुये उल्फा उग्रवादी	5
(3)	बरामद किये गये शस्त्र	441
(4)	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	1269

(ख) राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद बरामद किये गये शव 26

(ग) अलग अलग रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं और वास्तविक आंकड़े देना बहुत कठिन है।

(घ) तथा (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार उल्फा के लोगों ने सीमापार उग्रवादी समूहों से प्रशिक्षण तथा हथियार प्राप्त किये।

Constitution of Vidarbha, Marathwada and Konkan Statutory Development Boar

507. DR. BAPU KALDATE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the former Prime Minister, Shri Vishwanath Pratap Singh, had, on the 15th August, 1990 announced Government's intention to constitute Vidarbha, Marathwada and Konkan Statutory Development Board under Article 371(2) of the Constitution;

(b) whether Government propose to bring any legislation in this regard;

(c) if so, what steps have been taken in this regard;

(d) if the reply to part (b) above be in the nagative, what are the reasons therefor;

(e) whether backward regions in Bihar, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh have also been identified for constituting statutory development boards in those States; and

(f) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) Yes, Sir.

(b), (c) and (d) The earlier proposal of the Government of Maharashtra was for issuing President's Order in terms of article 371(2) of the Constitution to facilitate establishment of separate Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra. The revised proposal suggests inclusion of Konkan in article 371(2) and for making a change in the provision relating to "the special responsibility" of the Governor. The proposals have been examined in the Ministry.